ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

रविवारीय, 01 - 07 दिसंबर 2019, वर्ष- एक, अंक-17, रांची | हिन्दी साप्ताहिक | R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 | कुल पृष्ठ 4 | मूल्य 2 रूपये

पेजः 4

सागों का सरदार है बथुवा

झारखंड राज्य में पर्यावरण, प्रदूषण, कृषि, ग्रामीण विकास एवं सामाजिक विषयों पर डॉक्युमेंट्री बनाने के लिये संपर्क करें

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

चेंबर ने दावा किया था कि प्याज का पर्याप्त स्टॉक है फिर भी खुदरा में 80-90 रू किलो बिका रहा है प्याज

प्याज का खेलः परत दर परत

वरीय संवाददाता

भारत में प्याज महज एक सब्जी नहीं है बल्कि राजनीतिक फसल भी है। यहां प्याज के कारण सरकारें बन और गिर जाती हैं। दिल्ली में एक बार प्याज की बढी हुई कीमत के कारण भाजपा सरकार को चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा था। प्याज की कीमत बढने पर जोक्स, कार्टून और व्यंग्य की भरमार होने लगती है। अभी प्याज की कीमत ऊफान पर है और सरकार को कोसने, कालाबाजारी के साथ ही झारखंड के चुनावों में भी इसकी चर्चा है। चुनाव आयोग ने सरकार को सस्ता प्याज उपलब्ध करवाने से रोक दिया है। आखिर हर साल दो साल पर प्याज की कीमते आसमान क्यों छूने लगती है ?क्या है इसकी परत दर परत हकीकत?

कहां से आया प्याज?

आलू, मिर्च, अनानास विदेशी फल और सब्जियां हैं और ये सभी पुर्तगालियों और अंग्रेजों के भारत में लाये हुये हैं, पर ऐसा माना जाता है कि प्याज की उत्पति मध्य एशिया में हीं कही हुई । दुनिया में 45 प्रतिशत प्याज उत्पादन अकेले भारत और चीन करते हैं। और इसका नब्बे प्रतिशत खुद खा जाते हैं। चीन में एक-एक किलो आकार के बड़े प्याज भी होते हैं जो बेस्वाद होते हैं। भारत में प्याज की कमी होने पर यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और मिस्त्र से आयात होता है। प्याज दुनिया भर के रसोई की मुख्य सब्जी है और बगैर इसके कहीं भी भोजन नहीं बनता। भारत में नासिक सबसे बड़ी प्याज मंडी है। यहां प्याज कि तीन मुख्य किस्में हैं सफेद,गुलाबी और कत्थई । सफेद प्याज से औषधियां बनाई जाती हैं।

क्यों महंगा हुआ प्याज ?

वर्तमान में प्याज के दाम में उछाल की वजह उसके उत्पादन में 26 प्रतिशत गिरावट है। केंद्र सरकार ने प्याज की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए प्याज के आयात को मंजूरी दी है। आने वाले दिनों में आयातित प्याज के कारण दाम घटेंगे और विक्रेताओं को वर्तमान में मिल रहा लाभ कम हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में प्याज की कीमतें आम लोगों को रूला रही हैं। हकीकत में प्याज की कमी तो है ही, इसका अवैध भंडारण और पुरजोर मुनाफे के लिये बड़े व्यावसायियों द्वारा कृत्रिम कमी भी पैदा की गयी है तभी रांची में ही कहीं 80 और 100 रूपये किलो तो कहीं 50 रूपये किलो भी प्याज बिक रहे हैं।

कृत्रिम अभाव भी पैदा किया जाता है

प्याज एक ऐसी कृषि उपज है जिसके दाम में उछाल आने पर सरकारें सक्रिय हो जाती हैं। इस तरह की सक्रियता वर्तमान में देखी जा रही हैं लेकिन सरकारें तब कुछ नहीं करतीं, जब इसके दाम में इतनी गिरावट आ जाती है तब किसानों को प्याज फेंकनी पड़ती है। कई बार प्याज के भाव इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि उसका कृत्रिम अभाव पैदा कर दिया जाता है। किसान प्याज को मंडी में बेच आते हैं लेकिन बिचौलिए उसका भंडारण कर कृत्रिम अभाव पैदा कर देते हैं। इससे प्याज का भाव बढ़ जाता है और इसका पूरा फायदा बिचौलिए उठा लेते हैं। बिचौलिए सीमित मात्रा में प्याज निकालकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। इस तरह जो फायदा किसानों को मिलना चाहिए, वह उन्हें नहीं मिल पाता। भ्रष्टाचार और सरकारी तंत्र की मिलीभगत से यह कृत्रिम अभाव पैदा किया जाता है।

रांचीवासियों को नहीं मिला सस्ता प्याज

झारखंड सरकार ने प्याज की बढती कीमत देख भंडारण पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया और बिस्कोमान ,नेफेड की मदद से रांची में लोगों को 35 रूपये किलो प्याज उपलब्ध कराने शुरू कर दिये। विपक्ष ने आपत्ति जता दी और विधानसभा चुनावों के कारण चुनाव आयोग ने सस्ते प्याज बेचने पर रोक लगा दी। जिससे सस्ते प्याज पर लगाम लग गया। अब यहां 80-100 रूपये खुदरा प्याज बिक रहा है, जबकि कहीं-कहीं बड़े बाजारों में 50-60 रूपये किलो बिक रहा है।

सीसीआई की पड़तालः व्यापारियों का है खेल

उत्पादन और रकबा बढने के बाद भी प्याज महंगा क्यों?

प्याज अकेली उपज है जिसका व्यापार अन्य फसलों से काफी अलग है। कई बार बाजार के नियम उसके आगे बौने साबित हुए हैं। 2012 में प्याज की इसी प्रकृति को समझने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को पड़ताल करनी पड़ी थी। सीसीआई ने यह पता लगाया कि आखिर उत्पादन और रकबा बढ़ने के बाद भी प्याज का दाम क्यों बढ़ जाता है? कर्नाटक और महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण बाजारों का अध्ययन करने के बाद सीसीआई के शोधकर्ताओं ने पाया कि प्याज के उत्पादक, आवक और भाव के बीच कोई संबंध नहीं है। उन्होंने पाया कि कुछ महीनों में प्याज की आवक सर्वाधिक होने के बाद भी उसके भाव अधिकतम रहते हैं। नीति निर्माताओं के लिए यही बात सिरदर्दी वाली है सीसीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ''यह स्पष्ट है कि मंडी में प्याज की प्रतिदिन की आवक का सभी मंडियों में उसकी कीमत से कोई संबंध नहीं है। अर्थात इन बाजारों में प्याज के भाव का प्रचुर उपलब्धता से कोई संबंध नहीं है।'' सीसीआई के शोधकर्ताओं ने पाया कि प्याज अपने व्यापारियों की शिकार है जो अधिकतम लाभ की लालसा में किसानों को भारी नुकसान और उपभोक्ताओं को बढ़ी कीमतों के बोझ तले दबा देते हैं।

5800 पेड़ लगा चुकी है टीम ग्रीन

संवाददाता

राज्य में एक ओर सरकार विकास के निर्माण पर हजारों पेड़ों को रातोरात धराशायी कर रही हैं वहीं रांची के कुछ युवा निःस्वार्थ भाव से टीम ग्रीन के माध्यम से वृक्षारोपण के काम में लगे हुये हैं।

टीम ग्रीन क्या है?

टीम ग्रीन रांची के कुछ युवा वर्ग के समूह के सहयोग से निर्मित एक संस्था है जो पौधारोपण का कार्य करती है। पर्यावरण सरक्षण के उद्देश्य से बनी यह संस्था प्रत्येक रविवार को शहर के विभिन्न इलाकों मे पेड़ लगाने का कार्य करती है। दिनांक 16 जून को 22 पौधे लगा कर शुरुआत करने वाली यह संस्था ने अब तक रांची तथा आस पास के इलाकों मे लगभग 5800 पेड़ लगा चुकी है और इनकी देख रेख का भी जिम्मा खुद उठाती है। ''गो ग्रीन बिफोर द ग्रीन गोज़'' का संदेश लिए यह संस्था हर रविवार जहां लोग घरों में छुट्टियां बिताना पसंद करते है वहां टीम ग्रीन हाथों में फावड़ा और पौधे लेकर पौधारोपण में अपना सहयोग देना पसंद करती है। जून में बनी इस संस्था के संस्थापक रांची के ही निवासी राहुल दयाल तथा निपुण जैन है। वर्तमान में इस संस्था से 150 से अधिक लोग जुड़े हुये है जिसमे विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायी तथा छात्र है। .....शेष पेज 3 पर

आप भी जुड़ सकते हैं टीम ग्रीन से

इस मुहिम के संबंध में इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थान किसी भी सहयोग हेतु टीम ग्रीन के वेबसाइट www.theteamgreen.com < http://www.theteamgreen.com> तथा 7739194444 के माध्यम से संपर्क कर सकते है। इसके अलावा फ्रेसबूक, ट्विट्टर तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी संस्था के मुहिम से जुड़ा जा सकता है।

भारत स्काउट एंड गाइड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की वार्षिक बैठक

संवाददाता

रांचीः 28नवंबर को रांची रेल मण्डल के मण्डल सभागार में भारत स्काउट एंड गाइड की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की वार्षिक बैठक मण्डल रेल प्रबन्धक सह भारत स्काउट एंड गाइड के अध्यक्ष नीरज अंबष्ठ की अध्यक्षता में हुई । मण्डल रेल प्रबन्धक ने कहा की '' रेलवे की सभी प्रकार की गतिविधियों तथा दुर्घटना, किसी भी प्रकार की जागरूकता आदि में भारत स्काउट एंड गाइड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है । इस संगठन के लिए हर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया। इस मौके पर अपर मंडल रेल प्रबंधक एम एम पंडित, अपर मंडल रेल प्रबंधक इन्फ्रा अजीत सिंह यादव ,वरिष्ठ मंडलअभियंता ,अमित कंचन, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सह मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नीरज कुमार, वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक अवनीश , मण्डल लेखा अधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह ,मंडल कार्मिक अधिकारी एस श्रीनिवास व अन्य उपस्थित थे।

लोक उद्यम चयन बोर्ड के अवर सचिव अजित कुमार मे किया मेकॉन का दौरा

लोक उद्यम चयन बोर्ड के अवर सचिव श्रीमान अजित कुमार ने भारत सरकार के उपक्रम मेकॉन लिमिटेड मे सोमवार को दौरा किया । श्रीमान अजित कुमार ने तकनीकी निदेशक पीके सारंगी व वित निदेशक आर एच जुनेजा से मुलाक़ात की । संजीव कुमार ने अजित कुमार का स्वागत किया और मेकॉन के बारे मे स्लाइड शो के माध्यम से जानकारी दी । वही विभिन्न विभागो का दौरा किया जिसमे सरंचना, कोक ओवेन, ब्लास्ट फर्निश, व पर्यावरण विभाग की कार्यप्रणाली को समझा । और मेकॉन तकनीकी के क्षेत्र में देश हित मे दिये गये अहम योगदान की सराहना की ।

मुख्य सचिव ने भवन निर्माण विभाग की चालू योजनाओं की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए कहा

सरकारी खर्च पर आवासों के निर्माण पर रोक

संवाददाता

- **भवन निर्माण विभाग को नई पॉलिसी बनाने का निर्देश।**
- **शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर बड़े-बड़े आहाता वाले पुराने भवनों को तोड़ बनेगा ओपेन स्पेस**
- **ओपेन स्पेस, ग्रीन स्पेस या पार्किंग स्पेस बनाने पर जोर**

रांचीः मुख्य सचिव डॉ. डी के तिवारी ने बिना किसी सुनिश्चित प्लान के आवास और कार्यालय भवन बनाने की परिपाटी पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि निर्माण के बाद भवनों का रख-रखाव एक समस्या होती है और इस पर सरकारी राशि खर्च होती है। पब्लिक मनी के सही उपयोग के लिए मोनेटाइजेशन (मुद्रीकरण) के माध्यम से पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड में जाया जा सकता है। मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी झारखण्ड मंत्रालय में भवन निर्माण विभाग की चालू योजनाओं और अगले वर्षों की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए यह बात कही। मुख्य सचिव ने बड़े लॉन वाले सरकारी घरों के कल्चर को भी हतोत्साहित करने पर बल दिया। वहीं राजधानी सहित जिला मुख्यालयों में अलग-अलग चल रहे पुराने कार्यालय भवनों को तोड़कर उन्हें एक जगह करने की योजना पर काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जहां से सरकारी भवन तोड़े-हटाएं जाएं, उस स्थान का उपयोग ओपेन स्पेस, ग्रीन स्पेस या पार्किंग स्पेस के रूप में करें। उन्होंने इन सभी को ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण विभाग को एक स्पष्ट नीति तैयार करने का निर्देश दिया।

किसी भी नये भवन का स्वीकृत्यादेश से पहले सभी क्लीयरेंस प्राप्त कर लें

मुख्य सचिव ने भवन निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि जब भी कोई नया भवन बनाने की जरूरत पड़े, उसके पहले सभी तरह का क्लीयरेंस लेने के बाद ही निर्माण का टेंडर निकालें व स्वीकृत्यादेश दें। उन्होंने केंद्र सरकार सहित विभिन्न राज्यों का उदाहरण देते हुए नये भवन निर्माण पॉलिसी में अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए पंचायत से लेकर राजधानी तक आवास निर्माण कर देने की जगह आकर्षक आवास किराया भत्ता दें। उन्होंने कहा कि सरकारी आवास तो बन जाते हैं, लेकिन लोग उसे लेने में बहुत कम लोग रुचि दिखाते हैं। *.....पेज 3 भी देखें*

मेकॉन में सतर्कता जागरूकता सप्ताह और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन

रांची : भारत सरकार के उपक्रम मेकॉन लिमिटेड रांची स्थित मुख्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का समापन व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम में सीएमडी अतुल भट्ट, आर एच जुनेजा (निदेशक वित्त), उपकार कुमार केडिया (मुख्य सतर्कता अधिकारी), उच्च अधिकारीगण तथा अन्य कर्मीगण, पुरस्कार विजेता छात्र-छात्राएँ तथा उनके शिक्षकगण उपस्थित थे। इस अवसर पर विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए तथा कार्यक्रमों में शामिल अधिकारियों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। गौतलब है कि पहले दिन मुख्यालय, रांची में सीएमडी अतुल भट्ट द्वारा उपस्थित कर्मियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गयी। माननीय उप-राष्ट्रपति, एवं सतर्कता आयोग के सन्देश क्रमशः मेकॉन के सीएमडी अतुल भट्ट, सीवीओ यू के केडिया द्वारा पढ़कर सुनाये गए ।

सेवानिवृत हुये रेलकर्मी को भावभीनी विदाई दी गयी

रांची : दिनांक 30 नवंबर 2019 को रांची रेल मंडल के ऑपरेटिंग विभाग में कार्यरत राम लखन सहायक, कंट्रोल ऑफिस 40 वर्षों की लंबी सेवा अवधि के बाद सेवानिवृत्त हुए ।

मिलनसार स्वभाव के धनी राम लखन बहुत ही अनुशासित व्यक्ति है तथा कार्य के प्रति हमेशा समर्पित रहे आज सेवानिवृत्ति के अवसर पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई तथा उज्जवल भविष्य की कामना की गई । विदाई के अवसर पर राम लखन जी के अलावा अन्य कर्मचारी भी भावुक हो गए । इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सह मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नीरज कुमार, मंडल परिचालन प्रबंधक मनोज कुमार सिंह,प्रधान मुख्य नियंत्रक के के हलधर एवं अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे ।

फसल बीमा योजनाओं का घटता आकर्षण

मुरलीधर

चार निजी बीमा कंपनियों द्वारा सरकार की प्रमुख फसल बीमा योजना-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) से बाहर जाने का निर्णय कतई चौंकाने वाला नहीं है। कृषि क्षेत्र में बीमा योजनाएं सन 1970 के दशक के आरंभ से ही अपनाई जाती रही हैं। यह सच है कि इस योजना को ऐसी अन्य योजनाओं की तुलना में अधिक सफलता मिली है लेकिन यह भी कुछ ऐसी कमियों की शिकार है जिनके चलते यह न बीमाकर्ताओं के लिए आकर्षक रह गई और न ही किसानों के लिए। बीमा कंपनियों को यह घाटे का सौदा लगती है, सरकार द्वारा 90 फीसदी की भारी सब्सिडी के बावजूद किसान शिकायत करते हैं कि उन्हें मिलने वाला हर्जाना बहुत कम है और लंबे अंतराल के बाद मिलता है। आम धारणा है कि बीमा कंपनियां अनुचित तरीके से सब्सिडी का लाभ ले रही हैं। यह आंशिक सच है। सन 2016 में योजना के शुरुआती वर्ष में मौसम के कारण फसल को नुकसान भी कम हुआ और इसलिए हर्जाना भी कम चुकाना पड़ा। इससे बीमाकर्ताओं को अच्छा मुनाफा हुआ। परंतु तब

से हालात में बदलाव आया और 2018 में बारिश सामान्य से 9 फीसदी कम और 2019 में 10 फीसदी ज्यादा हुई। इससे कई राज्यों में फसल को भारी नुकसान पहुंचा। यही कारण है कि हर्जाने के दावे संग्रहीत प्रीमियम से अधिक हो गए। इसका असर बीमा कंपनियों के मुनाफे पर पड़ा और फसल बीमा उनके लिए आकर्षक नहीं रह गया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के डिजाइन में कई कमियां हैं। इसमें बटाई पर खेती करने वाले किसानों की फसल के बीमा में बैंकों को अनिवार्य रूप से शामिल करना और नुकसान का आकलन हर किसान के लिए अलग से करने के बजाय एक तय इलाके में औसत फसल नुकसान के आधार पर करना शामिल है। बैंक प्रायः हर्जाने की राशि को बिना किसानों की सहमति के ऋण की राशि में समायोजित कर देते हैं। इसके चलते किसानों, बैंकों और बीमा कंपनियों के बीच भरोसा कमजोर पड़ रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार के साथ वित्तीय बोझ वहन करने में राज्य की समान भागीदारी की बात तथा फसल कटाई के प्रयोग के जरिये नुकसान का आकलन आदि भी दिक्कत पैदा कर रहे हैं। नुकसान के आकलन में तकनीक का प्रयोग भी वांछित तरीके से नहीं हो रहा है। इससे फसल नुकसान के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं और पुनर्भुगतान की राशि को अंतिम रूप देने में देर हो रही है। इतना ही नहीं राज्य अक्सर फंड में अपना हिस्सा देर से जारी करते हैं और वह भी किस्तों में। इसका असर नकदी की स्थिति और बीमा कंपनियों की भुगतान क्षमता पर पड़ता है। कई राज्यों ने सुनिश्चित राशि को बेहद कम रखा है जिससे लागत की भरपाई भी नहीं हो पाती। एक और बात यह है कि फसल बुवाई से लेकर कटाई तक कवरेज प्रदान करने वाली यह योजना मूल्य जोखिम की अनदेखी करती है जबकि वह किसानों के लिए अत्यंत आवश्यक है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हश्र भी ऐसी पुरानी योजनाओं जैसा नहीं हो, इसके लिए इन मुद्दों को समुचित तरीके से हल करना आवश्यक है। भारतीय किसान खासकर छोटे और सीमांत किसान जो बुरी तरह कर्ज में डूबे हुए हैं, उन्हें फसल बीमा की सख्त आवश्यकता है ताकि वे अपने जोखिम का बचाव कर सकें। बीमारियों, कीट-पतंगों और सबसे बढ़कर जलवायु परिवर्तन के चलते ये दिक्कत बढ़ती जा रही है। अतिरंजित मौसम की घटनाएं पहले ही बढ़ गई हैं। चक्रवाती तूफान जो पहले कभी-कभार आया करते थे वे हाल के दिनों में देश के तटीय इलाकों में आम हो गए हैं। इन घटनाओं ने पहले से नकदी की किल्लत झेल रहे किसानों को और परेशानी में डाला है। जब तक उन्हें एक सहज फसल बीमा जैसा विश्वसनीय जोखिम प्रबंधन नहीं मिल जाता, उनकी निराशा बढ़ती जाएगी।

रांची रेल मंडल में कस्टमर मीट का आयोजन

संवाददाता

रांची :रेल मण्डल के मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय स्थित सभागार में 27 नवंबर को एक कस्टमर मीट का आयोजन अपर मण्डल रेल प्रबंधक परिचालन एम एम पंडित की अध्यक्षता में किया गया। उन्होने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि- '' रेलवे के लिए अपने ग्राहकों की संतुष्टि सर्वोपरि है। एक दूसरे के सहयोग से ही सफलता संभव है । आपको कोई भी दिक्कत होती है तो रेलवे उसका समाधान करेगी। '' इससे पूर्व वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक अवनीश ने सभी का स्वागत किया। इस सभा में ग्राहकों के समस्याओं को सुना गया व सुझाव लिए गए। रेलवे के बकाया राशि के भुगतान पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर रेलवे के वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबन्धक सह जनसम्पर्क अधिकारी श्री नीरज कुमार, मण्डल लेखा अधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक देवराज बनर्जी , परिचालन एवं वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक उपस्थित थे।ग्राहको में एफसीआई, हिंडालको, गोदावरी , हटिया सा-ईडिंग, भारत पेट्रोलियम सहित कई कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे।

खान पान की बुरी लत

शहरी भारतीयों के खान पान में तेजी से बदलाव आ रहा है। वह ऑनलाइन भोजन मंगा रहे हैं, और युवा पिज्जा, बर्गर, हॉटडॉग के पीछे दिवाने हैं। हालांकि ऑनलाइन फूड का बाजार रोजगार भी पैदा कर रहा है, लेकिन अंततः यह सब देश का स्वास्थ्य ही खराब करेगा। भारत को अगर डायबिटिक कैपिटल कहते हैं तो इसके पीछे कुछ कारण भी हैं। हाल के कुछ दशकों में जैसे-जैसे भारतीयों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है वह यूरोप और अमेरिका की नकल करता गया है। अब आम भारतीयों के खाने में जंक फूड की मात्रा बढ़ती जा रही है।

यहां एक और तथ्य है जिसपर हम भारतीय कभी गौर नहीं करते। इन डिब्बा बंद , विदेशी या इनकी नकल में खुली भारतीय कंपनियों के फूड काउंटर पर मिलने वाले भोजन की क्वालिटी पर कोई ध्यान नहीं देता। अमेरिका में मिलने वाले कोकाकोला में जो प्रिजरवेटीव या फॉस्फोरस की मात्रा तय है वही मात्रा भारत में मिलने वाले कोकाकोला में खतरनाक स्तर तक चली जाती है। वहां फूड सेफ्टी के नियम कड़े हैं हमारे यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां चिकेन लेग विदेशों से तैयार कर डिब्बाबंद होकर जहाजों से कई दिनों बाद पहुंचता है जिसे भारतीय युवा चाव से खाता तो है, पर उसके क्वालिटी और खतरनाक प्रिजरवेटीव पर ध्यान नहीं देता। भारत में वैसे भी बड़े होटलों, रेस्टोरेंटो में मिलने वाले भोजनों पर आप आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। समय-समय पर यहां बड़े होटलों तक में घटिया, बासी, मिलावटी भोजन की शिकायतें मिलती रहती हैं। ऐसे में भारतीयों के खाने की यह नयी संस्कृति सारे देश का स्वास्थ्य खराब करेगी। अब तो गांव देहातों में भी बाजारों से देसी खान पान की चीजों के बजाय बासी, खतरनाक चाउमिन, चिल्ली और नकली सॉस के दूकानों की भरमार है। जो भारतीयों में पाइल्स रोग के बढने का मूल कारण है और हम भारतीयों का बीमार होना विदेशी दवा कंपनियों के लिये प्रयोग का सामान उपलब्ध होने सरीखा है। आखिर मधुमेह के मामले में भी तो हम इसी षडयंत्र का शिकार हुये हैं।

दशक भर पहले जब अमेरिका की पिज्जा, बर्गर, हॉटडॉग बनाने वाली कंपनियों ने भारत के हाइवे में अपनी दूकानें सजायीं तो उनकी बिक्री बहुत कम रही। दरअसल इन अमेरिकी कंपनियों को यात्रा के दरम्यान भारतीयों के खान पान की आदत का अंदाजा नहीं था। आम भारतीय यात्रा में सड़क किनारे ढाबों में बने गर्मागरम भारतीय व्यंजनों का लुत्फ लेता है वह पिज्जा बर्गर हॉट डॉग को तरजीह नहीं देता। नतीजनत इन अमेरिकी कंपनियों का बाजार कमजोर पड़ गया, तब इन्होंनें भारतीय मीडिया में ढाबों के खानों के गुणवत्ता पर सवाल उठवाये और कहा कि सड़क किनारे ढाबों में स्वास्थ्य के लिये खतरनाक भोजन परोसे जाते हैं, लेकिन उनका यह दाव भी फेल हो गया। आज स्थिति बदल रही है युवा वर्ग पिज्जा, हॉट डॉग, बर्गर का खाना आधुनिकता का सिंबल समझ रहा है जो कि है अंततः जंक फूड ही ।

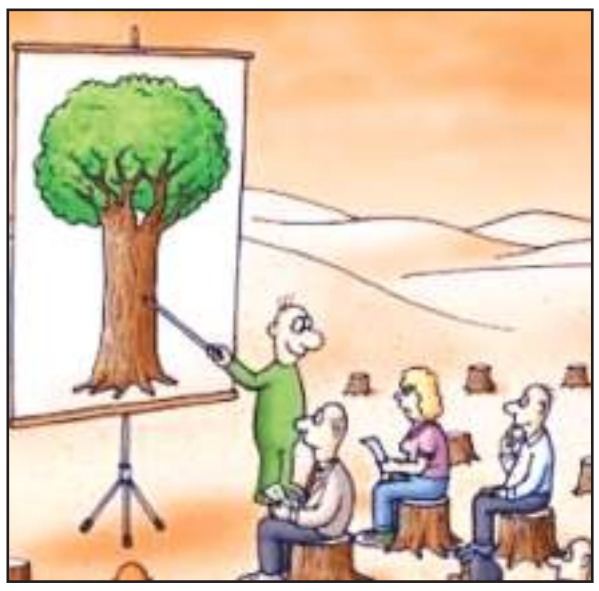

पराली जलाने में 29 किसानों पर एक लाख का जुर्माना

सेटेलाइट से हो रही निगरानी, छह के खिलाफ रिपोर्ट

एजेंसियां:हरदोई में पराली जलाने वाले किसानों के विरुद्ध रविवार को जिले की पांचों तहसीलों में अभियान चलाया गया। इस दौरान 29 किसानों पर 1 लाख 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं नोटिस के बाद भी पराली जलाने पर छह किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रदूषण की समस्या के कारण खेतों में पराली जलाने पर रोक लगा दी गई है। शासन स्तर से पराली जलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। रविवार को विशेष अभियान चलाया गया। उपनिदेशक कृषि डॉ. आशुतोष मिश्र ने बताया कि शाहाबाद तहसील क्षेत्र में छह, सवायजपुर में तीन, बिलग्राम में दो, संडीला में सात और सदर तहसील क्षेत्र में 11 किसानों पर कुल 1 लाख 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्हें पराली न जलाने की हिदायत दी गई है। उधर सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम भिठारी में एक बार नोटिस देने के बावजूद पराली जलाने वाले कमलेश पुत्र तौलेराम, रामकिशन पुत्र प्रभु, इंद्रपाल पुत्र भिखारी, जालंधर पुत्र द्वारिका, ऋषिराम पुत्र तौले, अजय कुमार पुत्र रामशंकर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है।सेटेलाइट से निगरानी, फौरन पहुंचती टीम पराली जलाने की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए निगरानी सेटेलाइट से की जा रही है। यही कारण है कि पराली जलने पर संबंधित क्षेत्र के अधिकारी सीधे खेत में पहुंच जाते हैं। उपनिदेशक कृषि डॉ. आशुतोष ने बताया कि किसानों को भ्रम था कि रविवार का अवकाश होने के कारण पराली जलाने की रोकथाम के लिए बने उड़नदस्ते क्षेत्र में नहीं पहुंचेंगे। लेकिन सेटेलाइट से पराली जलने की लोकेशन और फोटो मिलते ही टीमें संबंधित स्थानों पर पहुंच गईं।

जल परिवहन पर देना होगा अधिक ध्यान

***भारत में जल परिवहन में यह क्षमता है कि वह सामान लाने ले जाने की समस्या का समाधान कर सके। इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं* विनायक चटर्जी**

इस वर्ष जनवरी में केंद्रीय नौवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कांडला बंदरगाह से मंगलूरु और कोच्चि के रास्ते तूतीकोरिन तक के लिए कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकॉर)की तटीय माल नौवहन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यहां प्रयोग किए गए प्रतीक अत्यंत अहम हैं। कॉनकॉर भारतीय रेल की कंपनी है जो स्पष्ट रूप से तटीय नौवहन के लिए बनाई गई है। यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि दो केंद्रीय मंत्री (दो ऐसे मंत्री जो अहम बुनियादी क्षेत्रों के परिवहन को निर्धारित करते हैं) इस अवसर पर उपस्थित थे। इससे पता चलता है कि दो अलग-अलग तरह के परिवहन के आपसी संबंधों को किस कदर महत्ता दी जा रही है।

सितंबर में कॉनकॉर ने आंध्र प्रदेश के कृष्णापत्तनम बंदरगाह से बंगलादेश के चटगांव बंदरगाह तक माल नौवहन सेवा की शुरुआत की। इसके बाद सन 2018 में दोनों देशों के अधिकांश बंदरगाहों को दायरे में लाने के लिए इनलैंड वाटर ट्रांजिट ऐंड ट्रेड प्रोटोकॉल की शुरुआत हुई। ये कदम अपने आप में छोटे हैं लेकिन लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में बन रही व्यापक योजना की दृष्टि से ये काफी मायने रखते हैं। सड़क तथा रेल के अलावा अन्य मार्गों से माल ढुलाई की सुविधा लागत कम करने तथा भारतीय वस्तुओं को विश्व बाजार में अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दृष्टि से अहम है। अब तक जल मार्गों के इस प्रयोग पर ध्यान नहीं दिया गया था।

सड़क मार्ग से माल वहन की लागत प्रति टन किलोमीटर 2.58 रुपये पड़ती है जबकि रेल से यह 1.41 रुपये प्रति टन-किमी और जलमार्ग से 1.06 रुपये प्रति टन-किमी पड़ती है। इसके बावजूद देश में मालवहन का अधिकांश हिस्सा यानी करीब 60 फीसदी हिस्सा सड़क मार्ग के माध्यम से ढोया जाता है। चीन में मालवहन में सड़क की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत और जर्मनी में महज 11 प्रतिशत है। सड़क मार्ग पर जरूरत से अधिक निर्भरता के कारण हमारे देश में किसी उत्पाद के अंतिम मूल्य में लॉजिस्टिक्स की हिस्सेदारी 18 प्रतिशत तक है। विकसित देशों में यह बमुश्किल 9 से 10 प्रतिशत है। इतना ही नहीं सड़क परिवहन की तुलना में जलमार्ग से होने वाले परिवहन में प्रदूषण भी अत्यंत कम होता है।

ऐसे बदलाव की आवश्यकता सरकार बहुत लंबे समय से महसूस कर रही थी। वर्ष 2015 में उसने महत्त्वाकांक्षी सागरमाला परियोजना की शुरुआत की थी। इस परियोजना के तहत जलमार्गों में मालवहन की सुविधा विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। इस परियोजना में नए बंदरगाहों का विकास करना, बंदरगाहों का आपसी संपर्क कायम करना और उनके आसपास औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना शामिल था। इस प्रकार का संचार स्थापित करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। जलमार्गों के इस्तेमाल से लागत में होने वाली बचत गंवाई जा सकती है अगर जहाजों को टर्मिनलों पर खड़े होकर माल को ट्रक या रेल से जहाज पर पहुंचाए जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ी। चूंकि सागरमाला परियोजना की शुरुआत के बाद से कई अन्य सुधार भी शुरू किए गए हैं। केंद्रीय सड़क फंड अधिनियम में 2017 में संशोधन किया गया ताकि कुल संग्रहीत फंड के 2.5 फीसदी हिस्से का इस्तेमाल जलमार्ग विकास के लिए किया जाए। भारत में इस वक्त 14,500 किमी ऐसा जलमार्ग है जिस पर परिवहन किया जा सकता है। गत वर्ष के आरंभ में भारत सरकार ने नियमों को शिथिल करके विदेशी कंटेनर जहाजों को स्थानीय तटीय मार्गों पर माल ढुलाई करने की अनुमति दे दी थी। सरकार ने 1,500-2,000 टन भारवहन वाले जहाजों के नौवहन को लेकर जल मार्ग विकास परियोजना तैयार की है ताकि राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में हल्दिया से वाराणसी के बीच वाणिज्यिक परिवहन हो सके। इस परियोजना की लागत 5,369 करोड़ रुपये है।

अनुमान है कि यह परियोजना 2023 तक पूरी हो जाएगी। कॉनकॉर के रूप में तटीय नौवहन की शुरुआत के चंद महीने पहले इस क्षेत्र में उस समय एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एमवी रवींद्रनाथ टैगोर नामक जहाज का स्वागत किया। इस जहाज में पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी पेप्सी का 16 ट्रक माल कोलकाता से ढो कर लाया गया था। चार वर्ष की अवधि में सागरमाला परियोजना में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार का दावा है कि सितंबर तक इस योजना के अधीन 31,447 करोड़ रुपये मूल्य की 125 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसमें एन्नोर और मुंद्रा बंदरगाहों पर एलएनजी टर्मिनल (प्रत्येक की लागत करीब 5,000 करोड़ रुपये) और 6,600 करोड़ रुपये की लागत से जेएनपीटी बंदरगाह का उन्नयन शामिल हैं। परंतु अभी भी यह शुरुआती दौर है क्योंकि कुल मिलाकर 5.7 लाख करोड़ रुपये मूल्य की 1,314 परियोजनाएं अभी भी पाइपलाइन में हैं।

गत वर्ष सामने आए क्रिसिल के जगन्नारायण पद्मनाभन और सुदीप्त साहा के एक अनुमान के मुताबिक अगले कुछ वर्षों में जल परिवहन क्षेत्र में तकरीबन 90,000 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा। लेखकों ने जल परिवहन को प्रोत्साहन देने के लिए कर सब्सिडी देने की बात की थी। साथ ही जमीन पर स्थित टर्मिनलों पर कार्गो के किफायती निपटान की बात भी इसमें शामिल थी। राष्ट्रीय जलमार्गों के आसपास स्थित उद्योगों को प्रोत्साहन देने को भी एक विकल्प बताया गया है। दूसरी ओर सरकार कोयला तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थों के सड़क मार्ग से परिवहन पर भारी भरकम कर भी लगा सकती है। ऐसा करके वह ट्रांसपोर्टरों को लंबी दूरी के सफर के लिए जलमार्गों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। बहुत लंबे समय तक ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि नौवहन कंपनियों को सड़क से रेल मार्ग की ओर स्थानांतरित किया जाए। परंतु सागरमाला परियोजना में निवेश बढने तथा तमाम अन्य जरूरी नीतिगत बदलावों को मंजूरी मिलने के साथ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वास्तव में जलमार्ग एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी अनदेखी की जाती रही है। अब इस पर वह ध्यान दिया जा रहा है जिसके वे हकदार हैं। परंतु इस दिशा में और जोरदार तरीके से प्रयास करने की आवश्यकता है। ●

फसल अवशेष जलाने की समस्या का निदान

रमेश चंद

फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाने तथा पंजाब और हरियाणा के किसानों को धान की खेती के प्रति हतोत्साहित करना होगा।

कई वर्षों से दिल्ली तथा पश्चिमोत्तर भारत के अनेक हिस्सों में अक्टूबर और नवंबर में भारी प्रदूषण देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कई कारक हैं लेकिन प्रदूषण के इतने खतरनाक स्तर पर पहुंचने के लिए पड़ोसी राज्यों में धान की फसल के अवशेष जलाए जाने को वजह बताया जाता है। इस समस्या का स्थायी हल तलाशने के लिए हमें ऐसे विकल्प तलाशने होंगे जो किसानों को ऐसा करने से रोक सकें। पारंपरिक तौर पर फसल अवशेष का इस्तेमाल पालतू पशुओं के चारे या घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता था। इसके एक हिस्से से कंपोस्ट खाद बनाई जाती थी। समय के साथ फसल अवशेष की आपूर्ति बढ़ती गई और ईंधन तथा चारे के नए विकल्प आने से इसकी मांग कम होती गई। सूखे चारे की जगह हरे चारे ने ले ली और ईंधन में एलपीजी तथा अन्य स्रोत आ गए। इस क्षेत्र में एक दिक्कत यह भी है कि गैर बासमती धान के सूखे डंठल, गेहूं के डंठल की तुलना में बेहद खराब चारा माने जाते हैं। किसानों के पास इस अवशेष को जलाने या धरती में निपटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। किसानों का गेहूं के फसल अवशेष जलाना आम है। लेकिन उसका नुकसान इतना अधिक महसूस नहीं होता है क्योंकि गर्मियों के दिन में तेज हवाएं धुएं को जल्दी ही फैला देती हैं। परंतु एक एकड़ भूभाग की गेहूं उपज के अवशेष जलाने का भी पर्यावरण को उतना ही नुकसान होता है जितना कि एक एकड़ धान से। दुख की बात है कि इस तरफ बढ़ते रुझान को गंभीरता से नहीं लिया गया। यदि प्रभावी उपाय नहीं अपनाए गए तो आने वाले वर्षों में इसके गंभीर परिणाम होंगे। धान की खेती की बात करें तो अभी कुछ वर्ष पहले तक इसमें हार्वेस्टर का प्रयोग कम होता था और अधिकांश खेती हाथ से होती थी। हाथ से की जाने वाली खेती में धान की कटाई सतह से 6 से 10 सेमी ऊपर से होती थी। इससे अवशेष बहुत कम बचता और जुताई के बाद आसानी से निकल जाता। इसे एक कोने में इकट्ठा कर दिया जाता जहां यह समय के साथ अपघटित हो जाता। अब पंजाब में 94 फीसदी इलाके में हार्वेस्टर से खेती होती है। मशीन केवल ऊपर से 20 सेमी फसल काटती है और बाकी पौधा जस का तस छोड़ देती है। बचा हुआ अवशेष अगली फसल की तैयारी में मुश्किल पैदा करता है। धान कटाई के चार से छह सप्ताह बाद गेहूं की बुआई होती है। ऐसे में खेत को जल्दी साफ करना एक समस्या होती है। पंजाब में जहां 75 फीसदी खरीफ रकबा धान है और इसका भी 78 फीसदी हिस्सा जलाया जाता है, वहां यह समस्या ज्यादा गंभीर है। कुछ किसानों को इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा है और वे इस अवशेष को मिट्टी में दबाते हैं। इसके लिए इस अवशेष को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटना होता है ताकि उनको जुताई के दौरान मिट्टी में मिलाया जा सके। इससे उर्वरता बढ़ती है और अवशेष का अपघटन हो जाता है। यह अपघटन बहुत धीमी गति से ही सही लेकिन वातावरण में मीथेन उत्सर्जित करता है। इसमें किसान को पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। इसमें कई मशीन प्रयोग की जाती हैं और इसकी लागत करीब 3,000 रुपये प्रति एकड़ आती है। इसका बड़ा हिस्सा अगली फसल की लागत में जुड़ जाता है। केंद्र सरकार ने संबंधित मशीनरी की खरीद पर भारी सब्सिडी की व्यवस्था की है ताकि फसल अवशेष को मिट्टी में मिलाया जा सके। बहरहाल, लागत के चलते ऐसा हो नहीं पा रहा। इसके अलावा सब्सिडी भी चुनिंदा कंपनियों के उपकरणों पर है। आवश्यकता है कि देश के इस हिस्से में फसल अवशेष जलाने का दीर्घकालिक हल निकाला जाए।

इससे निपटने के लिए तीन तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला, फसल अवशेष से बायो-सीएनजी का उत्पादन। इस प्रक्रिया में उत्सर्जन भी न के बराबर होगा। बायोगैस निकालने के बार शेष बचा अवशेष खाद के काम आएगा। विशेषज्ञों से बातचीत से पता चलता है कि धान के डंठलों का सीएनजी के लिए इस्तेमाल किफायती है। इसकी प्रक्रिया भी पर्यावरण के अनुकूल है और इसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी नहीं होता। ऐसे निवेश के लिए रियायती दर पर ऋण की व्यवस्था की जानी चाहिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा पंजाब सरकार ने बायो-सीएनजी संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की थी लेकिन इस दिशा में कुछ खास प्रगति नहीं हुई है। पंजाब के संगरूर जिले में जर्मनी के निवेश से एक संयंत्र लगा है जबकि दूसरा हरियाणा के करनाल जिले में लग रहा है। केंद्र और राज्यों को बायो-सीएनजी संयंत्रों को बढ़ावा देना चाहिए और संयंत्र लगाने के इच्छुक पक्षकारों को जल्द और रियायती ऋण देना चाहिए।

दूसरा विकल्प है बायोमास के परिवर्तित स्वरूप को ताप बिजली घरों में कोयले के स्थान पर प्रयोग करना या औद्योगिक संयंत्रों में ईंधन के रूप में आजमाना। धान के प्रचुर उत्पादन वाले इलाकों में यह तरीका भी कारगर हो सकता है।

तीसरा विकल्प है बायोमास का शीघ्र अपघटन कर उसे जमीन में मिला देना। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक माइक्रोबायल फॉर्मूला बनाया है जो धान के बायोमास को 20-25 दिन में अपघटित कर देता है। अब वे इस तकनीक को खेतों में प्रयोग करने लायक बना रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह तकनीक जल्दी ही खेतों में प्रयोग के लिए तैयार होगी। इन विकल्पों के सहारे कचरे को संपत्ति में बदला जा सकता है यह धान के अवशेष जलाने से भी देश भर में छुटकारा दिला सकते हैं। बीते तीन दशक के दौरान हमारी खेती के तरीके में भी बदलाव आया है। इसके लिए कच्चे माल पर सब्सिडी और उत्पादन मूल्य नीति जिम्मेदार है। आज हम मांग से 10 फीसदी अधिक चावल उगा रहे हैं। जाहिर है ऐसा नीतियों के चावल उत्पादन के पक्ष में झुके होने से हो रहा है। इसका असर भूजल पर पड़ रहा है। इससे पर्यावरण खराब हो रहा है और राजकोषीय संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है।अब नीतियों में संशोधन कर पंजाब और हरियाणा को धान की खेती से विमुख करना होगा। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देना बंद करने और उस सब्सिडी को भिन्न स्वरूप में किसानों को देने से भी फर्क पड़ेगा।

(लेखक नीति आयोग के सदस्य हैं। लेख में उनके निजी विचार हैं)

बकरी के दूध से साबुन बनाकर जिंदगी संवार रहे हैं किसान

महाराष्ट्र के सुखाड़ इलाके उस्मानाबाद में किसान बकरियों के दूध की तदबीर से अपनी बिगड़ी हुई तकदीर बना रहे हैं। इस काम में उनकी मदद स्थानीय नस्ल की उस्मानाबादी बकरी कर रही हैं। करीब 25 गांवों का परिवार इस बकरी की मदद से साबुन बनाकर पैसे कमा रहा है। उनकी मदद कर रही स्वयंसेवी संस्था 'शिवार' के सीईओ विनायक हेगाना ने कहा, यह काम उन किसानों के लिए शुरू किया गया जिन्होंने गरीबी के चलते आत्महत्या कर ली या बुरे दौर का सामना कर रहे हैं। हेगाना ने कहा, पीड़ित परिवारों को हम आजीविका कमाने का तरीका बता रहे हैं। उस्मानाबादी बकरियों को पालकर मुनाफा कमा सकते हैं। किसानों को एक लीटर बकरी के दूध के 300 रुपये मिलते हैं और एक दिन के काम का 150 रुपया दिया जा रहा है। इस काम में 250 परिवार और उनकी 1400 बकरियां शामिल है। संस्था इस परियोजना में 10,000 और परिवारों को जोड़ेगी।

उस्मानाबादी बकरी ही क्यों?

विटामिन ए, ई, सेलेनियम और अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल से भरपूर बकरी का दूध त्वचा के रोगों के इलाज में बेहतर है। उस्मानाबादी बकरी का प्रयोग दूध और मांस दोनों के लिए होता है। इस नस्ल की बकरी महाराष्ट्र में पाई जाती है। इस नस्ल की मृत्युदर भी कम है।

क्या इस बार सर्दी कम पड़ेगी?

मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दिसंबर से फरवरी के बीच का सर्द महीना इस बार गर्म रह सकता है। 29 नवंबर को यह पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि जहां सामान्य तौर पर सर्दियों का मौसम औसत तापमान के मुकाबले गर्म होगा, वहीं शीत-लहर वाले क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में गर्म रहेंगे। विभाग ने कहा है कि दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 के दौरान कोर कोल्ड वेव (शीत लहर) जोन में सामान्य न्यूनतम तापमान से ऊपर रहने की अपेक्षाकृत अधिक संभावना है। भारत का शीत-लहर क्षेत्र उत्तर भारतीय राज्यों पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में असर करता है।

भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्याज खाना हुआ महंगा

अगर आप पाकिस्तान को फूटी आंखों से भी नहीं देख सकते तो आप ये जान कर सुकून महसूस कर सकते हैं कि वहां भी प्याज की कीमत सौ रूपये किलो है, पर ये भी याद रखिये कि कमी होने पर भारत में प्याज पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आयात भी होता है।

एजेंसियां :पाकिस्तान में कई लोगों ने टमाटर खाना बंद कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां एक किलो टमाटर का दाम 300 रुपये हो गया है। हालांकि इस संदर्भ में व्यापारियों का कहना है कि पिछले एक दिन में टमाटर का खुदरा दाम 240 रुपये प्रति किलो से कम होकर 200 रुपये प्रति किलो हुआ है। पाकिस्तान में लोगों ने जरूरत के हिसाब से एक या दो टमाटर खरीदना शुरू कर दिया है। 250 ग्राम टमाटर के लिए लोग 80 रुपये चुका रहे हैं। डॉन अखबार के मुताबिक, ना सिर्फ टमाटर बल्कि पाकिस्तान में प्याज का दाम भी बढ़ा है। विक्रेता एक किलो प्याज 90 से 100 रुपये में बेच रहे हैं। जबकि पहले यह 80 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रहा था। प्याज का खुदरा दाम 70 रुपये प्रति किलो है।

बांग्लादेश में प्याज का दाम

बांग्लादेश में प्याज की कीमतों ने आसमान छू लिया है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि बांग्लादेश में एक किलो प्याज के लिए लोग 260 टका यानी 220 रुपये चुका रहे हैं। वहीं भारत में एक किलो प्याज का दाम 60 - 70 रुपये के बीच है। आमतौर पर बांग्लादेश में एक किलो प्याज 30 टका यानी करीब 26 रुपये का मिलता था। यानी अब प्याज का दाम 10 गुना बढ़ गया है। बांग्लादेश की सरकार ने हवाई जहाज से तुरंत प्याज आयात करने का फैसला किया है। यहां प्याज का कितना संकट है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मैन्यू से इसे हटा दिया है। हसीना ने प्याज खाना बंद कर दिया है। इस संकट को देखते हुए वायु मार्ग से प्याज का आयात किया जा रहा है। बांग्लादेश मे प्याज की कमी भारत द्वारा निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध की वजह से हुई है। भारत ने ज्यादा बारिश की वजह से प्याज की फसल खराब होने के बाद सितंबर के आखिरी महीने में प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी थी।

इसलिए बढ़े प्याज के दाम

शनिवार को प्रधानमंत्री आवास में बने किसी भी व्यंजन में प्याज का इस्तेमाल नहीं हो सका। प्याज की कमी के कारण इसके दाम आसमान छू रहे हैं। भारत से निर्यात रोक दिए जाने की वजह से पड़ोसी देशों में प्याज के दाम बढ़े हैं।

भारत में ये कदम उठा चुकी है सरकार

भारत में प्याज की कीमतों के मद्देनजर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। प्याज की कीमतें थामने के लिए कच्ची और प्रसंस्कृत प्याज के आयात पर पहले ही प्रतिबंध लग चुका है। सरकार कारोबारियों पर स्टॉक लिमिट लगा चुकी है, जिससे जमाखोरी रोकी जा सके। इसके अलावा ग्राहकों को राहत देने के लिए सरकार ने 23.40 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज बेचा। सरकार अपने बफर स्टॉक में से 57,000 टन प्याज निकाल चुकी है। प्याज की कीमतों का बढना नयी बात नहीं है दो तीन साल पर प्याज इसी तरह से लोगों को रूलाता है।

रेलकर्मियों को संविधान की शपथ

रांची :रेल मण्डल कार्यालय के परिसर में मण्डल रेल प्रबन्धक श्री नीरज अंबष्ठ ने संविधान दिवस के अवसर पर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को भारत के संविधान के प्रस्तावना की शपथ दिलाई। मण्डल के सभी स्टेशनों/ अस्पताल /वर्कशाप और अन्य यूनिटों में भी भारत के संविधान के प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) एम एम पंडित, वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय), अमित कंचन, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सह मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नीरज कुमार, मंडल कार्मिक अधिकारी (इंचार्ज) एस श्रीनिवास व अन्य उपस्थित थे।

मेकॉन में सम्मान समारोह का आयोजन

संवाददाता

रांची :भारत सरकार के संस्थान मेकॉन में हिंदी पखवाड़े के विजेताओ के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस पुरस्कार वितरण समारोह में मेकॉन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अतुल भट्ट, निदेषक (वित्त), आर.एच.जुनेजा, मुख्य सतर्कता अधिकारी, यु.के.केडिया एवं महाप्रबंधकगण, संयुक्त महाप्रबंधकगण, उप महाप्रबंधक प्रभारीगण एवं प्रतिभागिगण उपस्थित थे।

इस कार्यक्रम का संचालन उप महाप्रबंधक प्रभारी (निगमित संचार व मानव संसाधन विकास) एवं राजभाषा संदीप सिन्हा ने किया। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेषक, अतुल भट्ट ने सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। निबंध प्रतियोगिता में कुमार गौरव, प्रथम, श्रीमती षिल्पी रंजन, द्वितीय, आन्नद कुमार झा, तृतीय एवं देवाषीष बोस तथा अभिषेक अड्डी को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। तात्कालिक भाषण में श्रीमती सीमन्तिनी साहु, प्रथम, कुमुद रंजन, द्वितीय, ललित कुमार सिंह, तृतीय, सुश्री तृषा सरदार एव सुश्री खुशबू सेहरा को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। कविता पाठ प्रतियोगिता में सुरेष कुमार, प्रथम, श्रीमती संगीता सेठी, द्वितीय, सुश्री मीनाक्षी मालवीय, तृतीय एवं सुश्री बिक्की तथा श्रीमती लक्ष्मी महतो को संत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि यह पुरस्कार कार्यक्रम हिंदी पखवाड़ा 14 सितम्बर से 28 सितम्बर को आयोजित निबंध प्रतियोगिता, तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता एवं कविता पाठ प्रतियागिता के लिए आयोजित किया गया और इसमे में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया गया ।

सीएमपीडीआई में संविधान दिवस मनाया गया

रांची : संविधान दिवस के अवसर पर सीएमपीडीआई के निदेससाक (तकनीकी/आरड-ाएंडटी/सीआरडी) श्री आर0एन0 झा द्वारा सभी उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारीगणों के बीच संविधान प्रस्तावना का वाचन करवाया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष सहित मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थान-3 के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

.....पेज 1 का शेष

सरकारी खर्च पर आवासों के निर्माण पर रोक

इससे आवास खाली रह जाते हैं और उनका सही रख-रखाव भी नहीं हो पाता। इससे अतिक्रमण की समस्या भी आती है। इसका भी निदान जमीन को मोनेटाइज (मुद्रीकरण) कर पीपीपी मोड पर हो सकता है। वहीं कार्यालयों के सामान्य मेंटेंनेंस आदि के लिए कार्यालय मद में ही हेड ऑफ द ऑफिस को एक निश्चित राशि देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसे ही देखते हुए नन प्लान बजट को जीरो किया गया है।

मुख्य सचिव ने राजधानी के कतिपय इलाके में बड़े-बड़े आहाता वाले भवनों और आवासों को तोड़ कर वहां ओपेन स्पेस, पार्किंग स्पेस या ग्रीन स्पेस डेवलप करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने रांची के न्यूकिलियस मॉल के पास दो सरकारी आवासों को हटाकर वहां मोनेटाइजेशन के तहत ट्रैफिक व पार्किंग आदि की समस्याओं को दूर करने हेतु मल्टी लेवल पार्किंग बनाने पर बल दिया। वहीं शहर के अन्य स्थानों पर स्थित ऐसे सरकारी भवनों को भी चिह्नित कर उनका उपयोग ओपेन स्पेस, ग्रीन स्पेस आदि में करने का निर्देश दिया। भवन निर्माण विभाग ने रातू रोड और डोरंडा के जर्जर भवनों को पहले से चिह्नित कर रखने की बात कही।

निगम को जरूरतों के अनुसार अपग्रेड करें, इस्टेट ऑफिसर रखें

मुख्य सचिव ने वर्तमान की जरूरतों के अनुसार भवन निर्माण निगम को अपग्रेड करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि निगम में एक इस्टेट ऑफिसर रखें, जो सभी भवनों का लेखा-जोखा रखेंगे। वहीं वे योजना विभाग से समन्वय बनाकर सभी विभागों के साथ इसकी भी व्यवस्था करेंगे कि किस निर्मित भवन को किसे हैंडओवर किया गया। उसका उपयोग शुरू हुआ या नहीं और उसका क्या उपयोग हो रहा है। उन्होंने आवासों-कार्यालय भवनों की पूरी जानकारी ऑनलाइन करने का भी निर्देश दिया। कहा, इससे पता रहेगा कि कौन आवास खाली है तथा किसमें कौन रह रहा है व कौन सा कार्यालय कौन चला रहा है।

इंजीनियर्स एकेडमी के लिए योजना बनाएं

मुख्य सचिव ने इंजीनियरों को जरुरतों के अनुसार अपडेट रखने के लिए भवन निर्माण विभाग को इंजीनियर्स एकेडमी के निर्माण की योजना बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने इंजीनियरिंग सेल की गहन समीक्षा करते हुए भवन निर्माण में उनकी उपयोगिता ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने पर बल दिया। निगरानी के काम को और मजबूत करने को कहा। नक्शा बनाने में शहर के वातावरण और उसकी संस्कृति आदि को भी ध्यान में रखने का निर्देश दिया। बाहर के कंसलटेंट इंजीनियरों की जगह अपने ही सेवानिवृत्त इंजीनियरों की सेवा लेने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नक्शा बनाते समय डिजायन, क्वालिटी के साथ कलर और थीम पर भी काम करें। इससे बार-बार बदलाव की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। उन्होंने एक बार फिर सचेत किया कि किसी भी हाल में भवनों का पक्का बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं हो, इसे सुनिश्चित करेंगे। उसकी जगह ग्रीन बाउंड्री वॉल करें।

भवन हैंडओवर के साथ अंतिम भुगतान तक की सूचना साझा करें

मुख्य सचिव ने भवन निर्माण के बाद उसे हैंडओवर करने से लेकर अंतिम भुगतान तक की स्थिति की सूचना संबंधित विभाग से साझा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भवन का उपयोग करनेवाले विभाग भी इससे संबंधित जानकारी देंगे कि वे कब से उसका उपयोग कर रहे हैं। इसकी समीक्षा योजना सह वित्त विभाग करेगा। वहीं निर्माण के हर स्टेज का समय तथा उसकी प्रगति की निगरानी पर जोर देते हुए कहा कि इसमें कोताही बरतने वाले ठेकेदारों पर आर्थिक दंड लगाएं।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, वित्त सह योजना विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के के खंडेलवाल, भवन निर्माण सचिव सुनील कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

रंगीन मछली पालन पर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

संवाददाता

रांची:कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) के अधीन कार्यरत मत्स्य अनुसंधान केंद्र के द्वारा रंगीन मछली पालन पर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शालीमार धूर्वा में आयोजित किया गया। विभाग द्वारा वर्ष 16-17 से लगातार महिलाओं को रंगीन मछली पालन कर स्वावलंबी बनाने के दिशा में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में रांची एवं जमशेदपुर में इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत एकल एवं समूह में महिलाओं द्वारा रंगीन मछली का पालन कर उन्हें बाजार में बेचा जा रहा है। विभाग द्वारा जिस महिला या समूह के पास खुद की दूकान है उन्हें 1 लाख रूपये व्यापार को आगे बढाने के लिये अनुदान भी दिया जा रहा है। विभाग के निदेशक डॉ. एच.एन. द्वीवेदी ने बताया कि जो महिला घर में ही रहती है उनके लिये यह बहुत ही उपयोगी योजना है। महिला सीमित

महिलाओं को प्रशिक्षण देते हुये विशेषज्ञ

जगह में इसका व्यवसाय कर रही हैं विभाग द्वारा रंगीन मछली पालन का उपकरण भी दिया जा रहा है। समूह अच्छा व्यवसास कर रही हैं। विभाग द्वारा एक आउटलेट भी खोला गया है जहां महिलायें तैयार रंगीन मछली दे देती हैं और उसे बाजार में बेच कर महिलाओं को उचित मूल्य दे दिया जाता है। कार्याशाला में आशीष कुमार उप मत्स्य निदेशक, मनोज कुमार सहायक मत्स्य निदेशक , अशेक कुमार सिंह सहायक मत्स्य निदेशक अनुसंधान , रणविजय कुमार,मधु स्वर्ण लकड़ा, सावनशील हंस एवं विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

रांची रेल मंडल के 11 कर्मी सेवानिवृत

●रेल ही एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां कर्मचारी के सेवानिवृति के दिन ही उसका समस्त पैसा उसे मिल जाता है।

संवाददाता

रांची :रांची रेल मण्डल के 11 रेलकर्मी सेवानिवृत हुए। इन सभी को सेवानिवृति से संबन्धित समस्त भुगतान किया गया। इस मौके पर अपर मण्डल रेल प्रबन्धक (परिचालन)एम एम पंडित ने कहा कि " रेलवे एक ऐसा संस्थान है जो अपने कर्मचारियों का पूरा ख्याल रखता है। यहाँ बहुत ही पारदर्शी तरीके से सभी चीजों का निपटारा होता है। सेवानिवृति के बाद भी यह अपने कर्मचारियों का ख्याल रखता है। आप अपना आगे का जीवन अपनी रुचियों को पूरा करने और परिवार के साथ बिताने में लगाएं।समारोह का संचालन सहायक मण्डल कार्मिक अधिकारी ऋषभ सिन्हा ने किया। सहायक मण्डल लेखा प्रबन्धक टीका राम मीना ने कहा कि '' अपने पैसे को सुरक्षित निवेश करें। सहायक मण्डल अभियंता (विद्युत) एम के मण्डल ने सभी को शुभकामनायें दीं। मेंस कांग्रेस के मण्डल समन्वयक चंचल सिंह ने इस मौके पर कहा कि ''रेल ही एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां कर्मचारी के सेवानिवृति के दिन ही उसका समस्त पैसा उसे मिल जाता है। सेवानिवृति के बाद भी अनेक प्रकार के लाभ कर्मियों को मिलते रहते हैं।

मण्डल सहायक कार्मिक अधिकारी मो अबरार ,मेंस यूनियन केदीपक कुमार इस मौके पर उपस्थित थे। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से अनुरोध किया गया कि अगर सेवानिवृत कर्मचारी बैंक से संबंधित कोई परिवर्तन करते हैं या अगर सेवानिवृत्त कर्मचारी अपना पता परिवर्तन करते हैं तो मंडल लेखा विभाग रांची को अवश्य सूचित करें । पीपीओ तथा मेडिकल कार्ड में पारिवारिक ब्योरा एक समान होना चाहिए भविष्य में संपर्क करने के लिए एक मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर अवश्य दें पीपीओ का एक प्रतिलिपि दिया गया है जिसमें पारिवारिक एवं अन्य विवरण दिया गया है ।कृपया जांच कर अगर कोई त्रुटि हो तो उसे शीघ्र लेखा विभाग को सूचित करें ।

सेवानिवृत कर्मियों के नाम --- नंदकिशोर भगत, राम लखन, बुधराम बानरा , मुकुट चंद्र देवघरिया, योगेंद्र नाथ सिंह, नरेंद्र प्रसाद सिंह, जय देव दत्ता, गणेश चंद्र कार,राजनाथ गिरी, मंडा सिंह मुंडा, फबिनिउस सोरेंग

.....पेज 1 का शेष

5800 पेड़ लगा चुकी है टीम ग्रीन

यह संस्था पिछले छह महीनों से अपने ही जेब खर्च तथा लोगो के सहयोग से विभिन्न इलाकों में पौधारोपण तथा इनकी देखभाल का मुहिम चला रही है जिनहे ये प्लांटेशन ड्राइव तथा केयर ड्राइव के नाम से संभोधित करते है। संस्था के इस निरंतर प्रयास को देखकर वर्तमान मेंवन-विभाग भी सहयोग को आगे आई है। टीम ग्रीन ग्रीष्म ऋतु में अपनी जलवायु से मशहूर रांची के बढ़ते तापमान के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को व्यक्त करने की एक छोटी सी प्रयास को एक मुहिम के जरिये आगे लेकर जाने के उद्देश्य से हमेशा लोगो को हर रविवार एक जनकल्याण कार्य से जोड़ती है तथा साथ ही साथ पेड़ लगाने के प्रति लोगों को व्हाट्सएप्प तथा फेसबुक के माध्यम से जागरूक भी करती है। संस्था ने न केवल सिर्फ पौधे लगाने पर प्राथमिकता दी है परंतु स्थानीय लोगो तथा संस्थानो द्वारा इनकी देखभाल के लियु भी हमेशा से प्रयासरत रही है। टीम ग्रीन के इस जनकल्याण प्रयास को रांची के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय तथा मुख्यमंत्री द्वारा भी ट्विट्टर के जरिये प्रेरित किया गया है। शहर में निरंतर बढ़ती जनसंख्या तथा घटती हरियाली को मद्देनजर रखते हुये रांची को हरा-भरा बनाने हेतु इस अभियान को लोगो का बहुत समर्थन मिल रहा है।

ग्रीन टीम को महामहीम औरउपमहापौर से भी सराहना मिली

बच्चों ने 4000 से ज्यादा पॉलिथीन गायों के पेट में जाने से रोका

शिरीष खरे

आम दिनचर्या में प्लास्टिक के अंधाधुंध उपयोग से होने वाला प्रदूषण और उस से होने वाले नुकसान किसी शहर पर चाहे तेज तूफान की तरह नजर आता है। एक ऐसा तूफान जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है।

ब्रिटेन के एलन मैकआर्थर फाउंडेशन के अनुसार समुद्री विशेषज्ञों को आशंका है कि वर्ष 2050 तक समुद्र में मछलियों से अधिक प्लास्टिक होगी। दूसरी तरफ, अपने सुंदर समुद्री तटों के कारण पूरी दुनिया के पर्यटकों को लुभाने वाला गोवा राज्य भी प्लास्टिक-कचरे के प्रकोप से अछूता नहीं है। यहां भी यह विकराल रूप में विकसित हो रहा है।

ऐसे में, गोवा की राजधानी, पणजी से करीब 25 किलोमीटर दूर बिचोलिम तहसील के अंतर्गत आने वाली शिरगाव की सरकारी प्राथमिक स्कूल के बच्चों ने एक नई उम्मीद जगाई है। यहां की तीन शिक्षिकाओं ने बच्चों को अपने आसपास के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ऐसा मंत्र दिया है कि बच्चे तो बच्चे, बच्चों के परिजन, फेरीवाले, दुकानदार, पंच-सरपंच से लेकर पूरे के पूरा गांव ही 'प्लास्टिक हटाओ' अभियान में शामिल हो गया है।

इस अभियान की विशेषता यह है कि इसमें पॉलिथीन जैसी चीजों को हटाने की बात तो होती ही है, साथ ही लोगों को उसके विकल्प भेंट भी किए जाते हैं। यहां के स्कूल के बच्चे और उनके परिजन हर साल हजारों की संख्या में प्लास्टिक-रहित बैग और पैकेट तैयार करते हैं और उन्हें जरुरतमंद लोगों को निःशुल्क बांटते हैं। यही वजह है कि स्कूल परिसर से शुरु हुआ यह अभियान अब घर, दुकान, मंदिर, सड़क, गली, मोहल्लों और चौराहों से होते हुए सभी सार्वजनिक स्थानों पर अपना प्रभाव दिखा रहा है।

बीते दो वर्षों से जारी यह अभियान अब एक ऐसा मॉडल बन चुका है कि यदि इसी तरह से गोवा का हर स्कूल ऐसा ही प्रयास करे और उन्हें स्थानीय प्रशासन एवं लोगों का साथ मिले तो गोवा को प्लास्टिक-मुक्त बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। शिरगाव करीब ढाई हजार की आबादी वाला गांव है। यहां अधिकतर निम्न-मध्यम वर्गीय किसान और मजदूर परिवार रहते हैं। वर्ष 1962 में स्थापित शिरगाव की इस मराठी माध्यम की पाठशाला में पहली से चौथी कक्षा तक कुल 29 बच्चे पढ़ते हैं। यहां प्रधानाध्यापिका सहित तीन शिक्षिकाएं हैं प्रेरणा का स्त्रोत

इस स्कूल परिसर के नजदीक प्रसिद्ध लईराई देवी का मंदिर है। यहां हर वर्ष अप्रैल के आखिरी दिनों में होने वाले जत्रोत्सव में गोवा सहित कई दूसरे राज्यों से करीब दस लाख श्रद्धालु आते हैं। स्कूल की प्रधानाध्यापिका, स्फूर्ति मांद्रेकर, दो वर्ष पहले की स्थितियों के बारे में बताते हुए कहती हैं कि उत्सव के बाद पूरी बस्ती में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक के कप, बोतलें और पॉलिथीन जमा हो जाते हैं। इसलिए, उन्हें हर समय लगता रहता था कि प्लास्टिक के इस बढ़ते प्रकोप को कम करना बहुत जरुरी है। यही सोचकर स्फूर्ति और स्कूल की अन्य शिक्षिकाएं कई वर्षों से प्लास्टिक के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाना चाहती थीं। लेकिन, चाहकर भी ये शिक्षिकाएं ऐसा कोई प्रयास नहीं कर पा रही थीं। इस बारे में पूछने पर स्फूर्ति बताती हैं, 'पहले हमें डर लगता था कि हमने ऐसा कुछ किया तो कहीं लोग हमारा ही विरोध कर हमसे यह न पूछने लगें कि आपका काम बच्चों को पढ़ाना है या क्या?' और यह भी बोल सकते हैं कि यह एक सरकारी अभियान है, तो यह काम सरकार को करने दो। आप अपना काम करो। फिर वर्ष 2017 में गोवा राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला। इसके तहत सौ से अधिक स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम लागू हुआ।

फोटो न्यूज

फोटोःश्रीमाली सुमी

पर्यावरण की रक्षा हेतु राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय कडरू में कुछ पौधारोपण की .. वहाँ पढ़ रहे छोटे बच्चों को पर्यावरण संबंधी जानकारी भी दी गयी..पौधों को लगाने से क्या लाभ है एवं पर्यावरण संरक्षण कितनी जरूरी है उसकी भी जानकारी दीः डॉ सुनीता यादव (समाज सेविका)

सागों का सरदार है बथुवा

अनुप सिंह

भारत को प्रकृति जितने प्रकार के शाक सब्जियों, मसालों और औषधीय जड़ी बूटी ने परिपूर्ण किया है शायद ही विश्व में किसी और देश के साथ ऐसा हुआ हो? भारत में सभी ऋतुएं होती हैं, यह समुद्र की सीमाओं वाला, बर्फिले पहाड़ों, नदियों के मैदानी उपजाउ भूमि वाला, घने जंगलों, पहाड़ों, पठारों और खनिजों से धरती का देश है और इसी कारण से यहां साग सब्जियों की भी विविधता देखने को मिलती है। इसी विविधता में एक महत्वपूर्ण औषधीय गुणों वाला स्वादिष्ट साग है बथुआ। हमारे भोजन में बथुये को कभी भी वह सम्मान नहीं मिला जिसका यह हकदार है। हालांकि झारखंड में बथुये को बहुत ही चाव से खाया जाता है।

सबसे अच्छा आहार है बथुवा

बथुवा अंग्रेजी में Lamb's Quarters, वैज्ञानिक नाम Chenopodium album. साग और रायता बना कर बथुवा अनादि काल से खाया जाता रहा है लेकिन क्या आपको पता है कि विश्व की सबसे पुरानी महल बनाने की पुस्तक शिल्प शास्त्र में लिखा है कि हमारे बुजुर्ग अपने घरों को हरा रंग करने के लिए प्लस्तर में बथुवा मिलाते थे और हमारी बुढ़ियां सिर से ढेरे व फांस (डैंड्रफ) साफ करने के लिए बथुवै के पानी से बाल धोया करती। बथुवा गुणों की खान है और भारत में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं तभी तो मेरा भारत महान है।

बथुये में क्या क्या है?? मतलब कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स??

तो सुने, बथुवे में क्या नहीं है? बथुवा विटामिन इ1, इ2, इ3, इ5, इ6, इ9 और विटामिन C से भरपूर है तथा बथुवे में कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम, मैगनीज, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम व जिंक आदि मिनरल्स हैं। 100 ग्राम कच्चे बथुवे यानि पत्तों में 7.3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 4.2 ग्राम प्रोटीन व 4 ग्राम पोषक रेशे होते हैं। कुल मिलाकर 43 गुणकारी तत्व होते हैं।जब बथुवा शीत (मट्ठा, लस्सी) या दही में मिला दिया जाता है तो यह किसी भी मांसाहार से ज्यादा प्रोटीन वाला व किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ से ज्यादा सुपाच्य व पौष्टिक आहार बन जाता है और साथ में बाजरे या मक्का की रोटी, मक्खन व गुड़ की डली हो तो इस खाने के लिए देवता भी तरसते हैं।

जब हम बीमार होते हैं तो आजकल डॉक्टर सबसे पहले विटामिन की गोली ही खाने की सलाह देते हैं ना??? गर्भवती महिला को खासतौर पर विटामिन बी, सी व लोहे की गोली बताई जाती है और बथुवे में वो सबकुछ है ही, कहने का मतलब है कि बथुवा पहलवानो से लेकर गर्भवती महिलाओं तक, बच्चों से लेकर बूढों तक, सबके लिए अमृत समान है।

यह साग प्रतिदिन खाने से गुर्दों में पथरी नहीं होती। बथुआ आमाशय को बलवान बनाता है, गर्मी से बढ़े हुए यकृत को ठीक करता है। बथुए के साग का सही मात्रा में सेवन किया जाए तो निरोग रहने के लिए सबसे उत्तम औषधि है। बथुए का सेवन कम से कम मसाले डालकर करें। नमक न मिलाएँ तो अच्छा है, यदि स्वाद के लिए मिलाना पड़े तो काला नमक मिलाएँ और देशी गाय के घी से छौंक लगाएँ। बथुए का उबाला हुआ पानी अच्छा लगता है तथा दही में बनाया हुआ रायता स्वादिष्ट होता है। किसी भी तरह बथुआ नित्य सेवन करें। बथुवै में जिंक होता है जो कि शुक्राणुवर्धक है मतलब किसी भाई को जिस्मानी कमजोरी हो तो उसको भी दूर कर दे बथुवा।बथुवा कब्ज दूर करता है और अगर पेट साफ रहेगा तो कोइ भी बीमारी शरीर में लगेगी ही नहीं, ताकत और स्फूर्ति बनी रहेगी। कहने का मतलब है कि जब तक इस मौसम में बथुए का साग मिलता रहे, नित्य इसकी सब्जी खाएँ। बथुए का रस, उबाला हुआ पानी पीएँ और तो और यह खराब लीवर को भी ठीक कर देता है। पथरी हो तो एक गिलास कच्चे बथुए के रस में शकर मिलाकर नित्य पिएँ तो पथरी टूटकर बाहर निकल आएगी।

मासिक धर्म रुका हुआ हो तो दो चम्मच बथुए के बीज एक गिलास पानी में उबालें । आधा रहने पर छानकर पी जाएँ। मासिक धर्म खुलकर साफ आएगा। आँखों में सूजन, लाली हो तो प्रतिदिन बथुए की सब्जी खाएँ। पेशाब के रोगी बथुआ आधा किलो, पानी तीन गिलास, दोनों को उबालें और फिर पानी छान लें । बथुए को निचोड़कर पानी निकालकर यह भी छाने हुए पानी में मिला लें। स्वाद के लिए नींबू जीरा, जरा सी काली मिर्च और काला नमक लें और पी जाएँ।

आप ने अपने दादा दादी से ये कहते जरूर सुना होगा कि हमने तो सारी उम्र अंग्रेजी दवा की एक गोली भी नहीं ली। उनके स्वास्थ्य व ताकत का राज यही बथुवा ही है। मकान को रंगने से लेकर खाने व दवाई तक बथुवा काम आता है और हाँ सिर के बाल ..... क्या करेंगे शम्पू इसके आगे। लेकिन अफसोस , हम किसान ये बातें भूलते जा रहे हैं और इस दिव्य पौधे को नष्ट करने के लिए अपने अपने खेतों में जहर डालते हैं।

तथाकथित कृषि वैज्ञानिकों (अंग्रेज व काले अंग्रेज) ने बथुवै को भी कोंधरा, चौलाई, सांठी, भाँखड़ी आदि सैकड़ों आयुर्वेदिक औषधियों को खरपतवार की श्रेणी में डाल दिया और हम भारतीय चूं भी ना कर पाये।और पढ़ लो अंग्रेजी और बन जाओ अंग्रेज, सुनो भाई जो ना सुधरे तो एक दिन इस जहर से कैंसर जैसी बीमारी हम सबको मारेगी क्योंकि हम इस स्वर्ग जैसी जमीन मे जहर डाल के नरक बनाने मे लगे हैं।

मवेशियों के टीबी रोग का टीका विकसित

इंग्लैंड स्थित सरे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मवेशियों में होने वाली टीबी (बोवाइन टीबी) के लिए एक नया टीका विकसित किया है। बोवाइन टीबी, मवेशियों के फेफड़ों को प्रभावित करने वाला एक संक्रामक रोग है। वैज्ञानिकों का यह शोध जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुआ है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने पहली बार एक टीका बनाया है, जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट (पीपीडी) के साथ उपयोग किया जा सकता है। यह ब्रिटेन में मवेशियों में टीबी की निगरानी के लिए कानूनी रूप से आवश्यक परीक्षण है। अभी तक मवेशियों में बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। यही वैक्सीन इंसानों में भी लगाई जाती है। चूंकि बीसीजी वैक्सीन का पीपीडी त्वचा परीक्षण के साथ उपयोग नहीं किया जा सकता है। जिन मवेशीयों को बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं, उनमें बोवाइन टीबी के रोगाणु माइकोबैक्टीरियम बोविस का पता नहीं चल पाता है। मवेशियों में बीसीजी का टीकाकरण इसलिए दुनिया के अधिकांश देशों में प्रतिबंधित है। मवेशियों की बीमारी के निदान के लिए पीपीडी त्वचा परीक्षण का उपयोग सबसे अच्छा विकल्प है। इस अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने एक नया बीसीजी स्ट्रेन वैक्सीन बनाने के बारे में सोचा। इस वैक्सीन में कुछ ऐसे प्रोटीन की कमी है, जिससे

माइकोबैक्टीरियम बोविस के रोगाणुओं के जीनों की पहचान की जा सकती है। साधारणतया इनमें एन्कोडेड इम्युनोजेनिक प्रोटीन होते हैं, जो बीसीजी से इसकी क्षमता को प्रभावित किए बिना हटाए जा सकते हैं। शोधकर्ताओं ने बीसीजी स्ट्रेन का टीका गायों को लगाया और इनके जीवित रहने की दर को मापा। इस परीक्षण ने टीम को उन जीनों की पहचान करने में मदद की, जिन्हें बीसीजी वैक्सीन की प्रभावशीलता से समझौता किए बिना हटाया जा सकता था।

गिनी पिग में नए बीसीजी स्ट्रेन टीके की सुरक्षा और प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया। गिनी पिग में सुरक्षित और तेजी से टीबी का उपचार हुआ। शोधकर्ताओं ने कहा कि बीसीजी का यह नया टीका पशु चिकित्सकों और किसानों को अपने जानवरों की रक्षा करने में मदद करेगा। मवेशियों में होने वाली टीबी (बोवाइन टीबी) को फैलने से रोकने के लिए, प्रभावी टीकाकरण और बीमारी कि सटीक शुरुआती जांच महत्वपूर्ण है। यह नया टीका मवेशियों में होने वाली टीबी से सुरक्षा प्रदान करता है और आगे भी इस घातक बीमारी से लड़ने में मदद करेगा। यह बीमारी दुनिया भर में 5 करोड़ से अधिक मवेशियों को संक्रमित करती है जोकि किसानों के लिए आर्थिक रूप से विनाशकारी है।

नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इनफार्मेशन के अनुसार, सन 2018 में भारत के लगभग 2.18 करोड़ मवेशी इस बीमारी से संक्रमित थे, यह संख्या तबके अमेरिका के डेयरी के गायों की कुल संख्या से अधिक थी। इस नए टीके से देश के करोड़ों मवेशियों को काल के गाल में जाने से बचाया जा सकता है।

नदियों के प्रदूषण को जांचने की नयी तकनीक

हवाई रिमोट सेंसिंग से भी नदियों में प्रदूषण के स्तर का पता लगाया जा सकता है।आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित प्रदूषण निगरानी की एक ऐसी ही तकनीक से गंगा नदी के जल की गुणवत्ता का पता लगाने में के वैज्ञानिकों को आरंभिक सफलता मिली है।

मोनोक्रोम सेंसर युक्त चार कैमरों को एक छोटे एयरक्राफ्ट पर लगाया गया था। वैज्ञानिकों ने नदी में प्रदूषकों की मौजूदगी को दर्शाने वाले परावर्तित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य को पृथक करने के लिए खास ऑप्टिकल फिल्टर्स और आंकड़ों का उपयोग किया है। फाल्स कलर कम्पोजिट विधि से नदी के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद तलछट या गाद के घनत्व का पता लगाने में भी वैज्ञानिक सफल हुए हैं।

आईआईटी-कानपुर के वैज्ञानिक प्रोफेसर राजीव सिन्हा ने बताया कि ड्रोन पर कैमरा लगाकर मल्टी-स्पेक्ट्रल और हाइपर-स्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक की मदद से गंगा में प्रवाहित किए जा रहे प्रदूषकों की प्रकृति और विशेषताओं का पता लगाने के लिए काम कर रही है।

युवाओं को है प्रदूषण की चिंता

संजय कुंदन

ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रेटा थुंबर्ग ही पर्यावरण बचाने की मुहिम में लगी हुई हैं। हमारे देश के युवा भी पर्यावरण संकट को समझते हैं और उससे निबटने को प्रयासरत भी हैं। महानगरों तक में अपनी वयस्तता के बीच से समय निकाल कर पर्यावरण के लिये काम करने वाले युवाओं का यह प्रयास सराहनीय है। क्या आप भी उनमें से एक हैं?

राजनेताओं के लिए भले ही प्रदूषण कोई मुद्दा न हो, वे भले ही संसद में इस पर चर्चा में शामिल न हों, लेकिन देश के युवाओं के लिए अब यह जरूरी मुद्दा बनता जा रहा है। युवाओं के बीच कराए गए एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। यंग जेनरेशन के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता है। पिछले दिनों सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग चेंज (सी3) और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनैशनल डिवेलपमेंट (यूएसएआईडी) ने एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण 'यूथ बोल' के नतीजे जारी किए। 10 महीने तक चले इस सर्वे में देश भर के 10 वर्ष से 24 वर्ष के एक लाख से अधिक बच्चों और युवाओं से पूछा गया कि वे अपने स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मुद्दों पर क्या विचार रखते हैं। 36 प्रतिशत युवाओं ने कहा कि उनकी प्राथमिकता शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है। 26 प्रतिशत युवाओं की सबसे बड़ी प्राथमिकता स्कूलों में कंप्यूटर, पुस्तकालय, भोजन, खेल के मैदान, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र, स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ हवा और पानी है।

साफ है कि युवाओं की प्रमुख आवश्यकताएं शिक्षा, रोजगार और पर्यावरण हैं। पर्यावरण रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन रहा है। स्कूल बंद होने की वजह से छोटे-छोटे बच्चे भी इसे जान रहे हैं। उन्हें यह अहसास हो रहा है कि प्रदूषण एक खतरनाक चीज है। स्वीडन की 16 वर्षीय पर्यावरण ऐक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को लेकर जो खबरें आईं उससे भी किशोरों के बीच पर्यावरण एक विषय बना। कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र ने बताया कि उनके एक रिश्तेदार की बेटी की शादी तय हुई है। लड़के वालों ने सामान वगैरह की मांग तो नहीं ही की, लड़के ने जरूर एक शर्त रखी कि खाने-पीने में प्लास्टिक की चीज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मेरे मित्र के रिश्तेदार इस चिंता में हैं कि पानी पीने के लिए किस चीज का ग्लास रखा जाएगा? मुझे लड़के की शर्त अच्छी लगी।

जिस तरह गांवों की कुछ लड़कियों ने जिद करके शौचालय बनवाए उसी तरह नौजवानों को पर्यावरण बचाने के लिए भी कुछ उपाय करने होंगे। दिक्कत यह है कि अभी बहुत सी चीजों का पता ही नहीं है। इसके लिए क्या-क्या किया जाए, लोगों को मालूम नहीं है। प्लास्टिक का पता चला है तो उसके खिलाफ अभियान चल रहा है। इसी तरह गाड़ियों के खिलाफ अभियान चल सकता है। अगर लाखों नौजवान छोटी दूरियों के लिए साइकिल से चलने की जिद ठान लें तो बदलाव क्यों नहीं आएगा। हाल तक पर्यावरण महज एक फैशन था। उस पर चित्र या प्रॉजेक्ट बनाना, दौड़ आयोजित करना वगैरह एक कर्मकांड जैसा लगता था। लेकिन अब चीजें उससे थोड़ा आगे बढ़ रही हैं, कारण यह है कि खतरा महसूस होने लगा है। दिल्ली-एनसीआर के पैरंट्स तो कहने लगे हैं कि हर साल एक से बीस नवंबर तक स्कूलों में 'स्मॉग ब्रेक' दिया जाए।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

- Repair your laptop with 3-month warranty.

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, ranchi
93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SunDAY Closed

ध्वनि प्रदूषण के कारण सिर्फ एकाग्रता ही भंग नहीं होती। इसके कई दूरगामी कुपरिणाम भी हैं। ध्वनि प्रदूषण के बीच रहने वाले व्यक्ति के स्तरीय काम करने की क्षमता कुछ इस तरह से प्रभावित हो जाती है कि वह बाद में शांत परिवेश में भी ठिक से काम नहीं कर पाता।

बाढ में भी फसल को बचायेगा रसायन

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय-रिवरसाइड की अगुवाई वाली टीम ने पौधों को पानी में खड़े रखने में मदद करने के लिए एक रसायन बनाया है, जो बाढ़, सूखा पड़ने पर फसल के नुकसान से बचा सकता है और बदलते मौसम के बावजूद किसानों को फसल उगाने और पैदावार बढ़ाने में मदद कर सकता है। प्लांट सेल जीवविज्ञान के प्रोफेसर शॉन कटलर ने कहा कि दुनिया भर में बाढ़ की इस होने फसलों के होने वाले नुकसान में अहम भूमिका होती है।

जल प्रदूषण दूर करने में मददगार हो सकता है प्लास्टिक कचरा

वैज्ञानिकों ने पॉलिएथलीन टेरेफ्थैलेट कचरे को ऐसी उपयोगी सामग्री में बदलने की रणनीति तैयार की है, जो पानी में जैव-प्रतिरोधक तत्वों के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने में मददगार हो सकती है। लखनऊ स्थित भारतीय विष-विज्ञान अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक कचरे से चुंबकीय रूप से संवेदनशील ऐसी अवशोषक सामग्री तैयार की है, जिसका उपयोग पानी से सीफैलेक्सीन नामक जैव प्रतिरोधक से होने वाले प्रदूषण को हटाने में हो सकता है। वैज्ञानिकों ने पॉलिएथलीन टेरेफ्थैलेट के कचरे को ऐसी उपयोगी सामग्री में बदलने की प्रभावी रणनीति तैयार की है, जो पानी में जैव-प्रतिरोधक तत्वों के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने में मददगार साबित हो सकती है। इस तकनीक से प्लास्टिक अपशिष्ट का निपटारा होने के साथ-साथ जल प्रदूषण को भी दूर किया जा सकेगा। अध्ययनकर्ताओं में शामिल डॉ. प्रेमांजलि राय ने बताया कि ''आसपास के क्षेत्रों से पीईटी रिफ्यूज एकत्रित कर नियंत्रित परिस्थितियों में उन्हें कार्बनीकरण एवं चुंबकीय रूपांतरण के जरिये चुंबकीय रूप से संवेदनशील कार्बन नैनो-मैटेरियल में परिवर्तित किया गया है।''डॉ. राय के अनुसार ''वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए कम लागत वाले इस नए चुंबकीय नैनो-मैटेरियल में प्रदूषित पानी से सीफैलेक्सीन को सोखने की बेहतर क्षमता है। अध्ययनकर्ताओं ने पाया है कि प्रति लीटर पानी में इस अवशोषक की 0.4 ग्राम मात्रा का उपयोग करने से सीफैलेक्सीन की आधे से अधिक सांद्रता को कम कर सकते हैं। इस खोज से अपशिष्ट प्रबंधन की गैर-अपघटन आधारित नवोन्मेषी रणनीतियां विकसित करने में मदद मिल सकती है।

आर्गेनिक उत्पादों का उत्पादन और खपत बढाना होगा

एजेंसियां: 27 नवंबर कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों ने खेती में बढ़ते रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त करते हुये जैविक खेती बढ़ाने पर जोर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यही स्थिति रही तो अगले पांच साल में रासायनिक उर्वरकों की खपत मौजूदा ढाई करोड़ टन से बढ़कर साढ़े चार करोड़ टन तक पहुंच जायेगी। इसका लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।विशेषज्ञों का कहना है कि 2025 तक देश में 30 करोड़ टन खाद्यान्न की जरूरत होगी और इसके लिये फसलों में रासायनिक उर्वरकों की खपत बढ़कर 4.5 करोड़ टन तक पहुंच जाएगी जो कि 1960 के दशक में सिर्फ दस लाख टन थी। विशेषज्ञों के अनुसार रासायनिक उर्वरकों की

स्वास्थ्य खतरों के संकेत

गैर सरकारी संगठन कट्स इंटरनेशनल के निदेशक जार्ज चेरियन ने बुधवार को यहां एक कार्यशाला में यह बात कही। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन में

बढोतरी के साथ साथ देश में रासायनिक उर्वरकों की खपत बढ़ रही है। खेती में उर्वरकों का उपयोग 1960 में 10 लाख टन था जो 2014-15 में बढ़कर 2.56 करोड़ टन पर पहुंच गया। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, 'देश में 2025 तक 30 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन के लिए 4.5 करोड़ टन उर्वरकों की जरूरत होगी। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 1960-70 में 8.67 प्रतिशत थी जो 2010 में 2.61 प्रतिशत रही। इसके साथ ही मिट्टी की उर्वरकता भी घट रही है।

चेरियन ने कहा, 'रासायनिक उर्वरक मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं इसलिए आर्गेनिक उत्पादन और खपत बढ़ाने की आवश्यकता है।प्रगतिशील किसान पद्मश्री जगदीश पारीक ने कहा कि किसान सब्सिडी के लालच में ऋण ब्याज के कुचक्र में फंस जाते हैं और फिर आत्महत्या करते हैं। उन्होंने कहा कि किसान शुरू में सरकारी सब्सिडी के आंशिक भुगतान के लिए उधार लेते हैं और उसके बाद ऋण ब्याज के दुष्चक्र में फंस जाते हैं।

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN/2019/78094, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।